



दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ

खबर नहीं, उसका अर्थ



देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम दौर में, पीयूष गोयल बोले रूपरेखा लगभग तैयार



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

ने कहा है कि समझौते की रूपरेखा लगभग तैयार है। उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि समझौते के क्रियान्वयन के बाद भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलना आवश्यक है। भारत और अमेरिका ने इसी वर्ष फरवरी

में प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में हुए बदलावों और अन्य व्यापारिक मुद्दों के चलते दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रही। अब वार्ता में भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी और अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियां सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय निर्यातकों के हित पर जोर पीयूष गोयल के अनुसार, भारत की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उचित परिस्थितियां मिलें। भारत के कई उत्पादों का मुकाबला दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से होने वाले निर्यात से होता है। ऐसे में शुल्क व्यवस्था और बाजार पहुंच

समझौते के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं। व्यापार समझौते का अंतिम स्वरूप दोनों देशों के बीच बातचीत और संबंधित शर्तों पर सहमति के आधार पर तय होगा। शुल्क, बाजार पहुंच और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े प्रावधानों पर होने के वाली चर्चा भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। उच्चस्तरीय बातचीत को मिलेगा नया दौर पीयूष गोयल आगामी जी-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। इस दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति सहित व्यापार से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत इस समय विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत आगे बढ़ा रहा है। इसका

व्यापक उद्देश्य भारतीय कंपनियों और निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच के अवसर बढ़ाना तथा वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को विस्तार देना है। अंतिम प्रावधानों पर रहेगी नजर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होने के बाद अब इसके अंतिम प्रावधानों और क्रियान्वयन से जुड़ी शर्तों पर होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होगी। विशेष रूप से शुल्क व्यवस्था और भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों की सहमति अहम मानी जा रही है। समझौते का अंतिम स्वरूप और उसके लागू होने की समयसीमा आगामी वार्ताओं और दोनों देशों की औपचारिक सहमति पर निर्भर करेगी। ऐसे में आने वाली उच्चस्तरीय बैठकों के परिणाम व्यापारिक जगत और भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

एशियन गेम्स में भारत का निशाना सटीक, सुरुचि- कमलजीत ने जीता स्वर्ण

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नागोया, 26 सितंबर 2026।

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुरुचि सिंह और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 484.6 अंक हासिल किए और इस स्कोर के साथ एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने 478.0 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि ईरान ने 415.8 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत की जीत का अंतर 6.6 अंक रहा। क्वालिफिकेशन में भी भारत सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल से पहले क्वालिफिकेशन दौर

में भी प्रभावी प्रदर्शन किया। भारतीय जोड़ी ने 587 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान के साथ पदक मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में भी दोनों ने अपने



प्रदर्शन की निरंतरता कायम रखी और शुरुआती दौर से बढ़त बनाए रखी। फाइनल के निर्णायक चरण में दक्षिण कोरिया की जोड़ी ने अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय निशानेबाजों ने दबाव के बीच संयम बनाए रखा और 484.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के बाद मिक्सड टीम में सफलता सुरुचि और कमलजीत के

लिए यह पदक इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दोनों को व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद मिक्सड टीम स्पर्धा में दोनों ने बेहतर तालमेल के साथ प्रदर्शन किया। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफिकेशन से लेकर फाइनल तक लगातार मजबूत प्रदर्शन किया। फाइनल में शुरुआती बढ़त को अंत तक कायम रखते हुए दोनों ने भारत का दूसरा स्वर्ण पदक इस जीत के साथ भारत के एशियन गेम्स 2026 अभियान में स्वर्ण पदकों की संख्या दो हो गई। यह इन खेलों में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक भी है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। सुरुचि और कमलजीत की जीत ने भारतीय निशानेबाजी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम में 484.6 अंकों का एशियन गेम्स रिकॉर्ड इस प्रदर्शन की प्रमुख विशेषता रहा।

SIR पर सियासी घमासान तेज, चुनाव आयोग से पारदर्शिता पर स्पष्टीकरण की मांग



भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच बहस तेज हो गई है। हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट

में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग सुखवीर सिंह संघू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के कुछ फ़ैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता नाम हटाने

और चुनावी डेटाबेस तक पहुंच जैसे विषय शामिल थे। आयोग के भीतर मतभेदों की रिपोर्ट से बड़ी चर्चा द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयोगों ने कुछ मामलों में निर्णय प्रक्रिया से पर्याप्त परामर्श नहीं होने तथा मतदाता डेटाबेस के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे उठाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ आपत्तियां नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस तक राज्य स्तर के अधिकारियों की पहुंच और SIR से जुड़े मामलों में अपील की प्रक्रिया को लेकर थीं। हालांकि, इन रिपोर्टों के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था-अलग विचार या टिप्पणियां सामने आना संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, SIR सहित महत्वपूर्ण निर्णय अधिरक्षित प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। विपक्ष ने मांगी जवाबदेही और स्पष्टता SIR को लेकर विपक्षी दल

लगातार चुनाव आयोग से अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध कार्यक्रमों की घोषणा भी की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की बात कही है। राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को प्रमाण और तथ्यों के साथ रखने की बात कही है। इस तरह SIR का मुद्दा अब केवल मतदाता सूची के प्रशासनिक पुनरीक्षण तक सीमित न रहकर चुनावी प्रक्रिया में संस्थागत पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास से जुड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। NDA के सहयोगी दलों ने भी मांगा स्पष्टीकरण दिलचस्प रूप से, चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग केवल विपक्ष की ओर से ही नहीं आई है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और तेलुगु देशम पार्टी जैसे NDA सहयोगी दलों ने भी SIR को लेकर उठ रहे सवाल पर आयोग से जनता के बीच स्पष्टता लाने की अपील की है।

भारत का कबड्डी में स्वर्णिम डबल, ईरान को हराकर पुरुष टीम ने फिर रचा इतिहास

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
आइची-नागोया, जापान, 26 सितंबर 2026। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 के

पुरुष कबड्डी में अपना खिताब बरकरार रखा और एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में नौवां स्वर्ण पदक हासिल किया। आइची-नागोया के टोकाई सिटीजन्स जिम्नेजियम में



फाइनल में ईरान को 40-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने

खेले गए फाइनल में भारत और ईरान के बीच शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ईरान

ने पहले हाफ में भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा और मध्यांतर तक 18-17 की बढ़त हासिल की। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने खेल की गति और रणनीति में बदलाव करते हुए मुकाबले पर पकड़ मजबूत की। रेडिंग में आक्रामकता और डिफेंस में बेहतर तालमेल के दम पर भारतीय टीम ने लगातार अंक जुटाए और ईरान की चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया। मुकाबले के निर्णायक दौर में भारत ने अपनी बढ़त कायम रखी। अंतिम सीटी बजने तक स्कोर 40-34 रहा और भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और फाइनल में भी दबाव के बावजूद संयम बनाए रखा। महिला टीम ने भी ईरान को हराकर जीता स्वर्ण भारत के लिए 26 सितंबर का दिन कबड्डी में दोहरी स्वर्णिम सफलता लेकर आया। ईरान के बीच शुरुआत से पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी

ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ महिला टीम ने एशियन गेम्स में अपना खिताब बरकरार रखा। इस तरह एशियन गेम्स 2026 में भारत ने कबड्डी के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किए। महिला टीम के लिए यह एशियाई खेलों में चौथा स्वर्ण पदक है। पुरुष टीम की जीत विशेष रूप से उल्लेखनीय रही क्योंकि ईरान एशियाई कबड्डी में भारत की प्रमुख प्रतिद्वंद्वी टीमों में शामिल रही है। 2026 के फाइनल में भी ईरान ने भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी, लेकिन दूसरे हाफ में भारत ने बेहतर सामंजस्य और प्रभावी खेल के जरिए मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। कबड्डी में दोनों स्वर्ण पदकों ने एशियन गेम्स में भारत के पदक अभियान को भी मजबूती दी है। पुरुष टीम की यह सफलता भारतीय कबड्डी के एशियाई खेलों में लंबे इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुई है।

दिल्ली में भक्ति का नया अंदाज, 'भजन क्लबिंग' में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम आयोजित 'भजन क्लबिंग' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पार्क में हुए इस आयोजन में पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत कार्यक्रम जैसी प्रस्तुति के साथ पेश किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दर्शकों के बीच अग्रिम पंक्ति में बैठे नजर आए। उन्होंने भक्ति गीत सुने, तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और एक



अन्य देवी-देवताओं से जुड़े भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। दर्शकों ने गीतों के साथ तालियां बजाकर और सामूहिक रूप से गाकर सहभागिता की। युवाओं के बीच उभरता सांस्कृतिक प्रारूप 'भजन क्लबिंग' को विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे भक्ति संगीत के नए प्रारूप के रूप में देखा जा रहा है। इसमें

पारंपरिक धार्मिक संगीत को आधुनिक मंचीय वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे युवा दर्शकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जनवरी 2026 में 'मन की बात' कार्यक्रम में भी भजन क्लबिंग का उल्लेख कर चुके हैं। उन्होंने इसे भक्ति, संस्कृति, आध्यात्मिकता और आधुनिकता के मेल के रूप में बताया था। दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर आयोजन यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती से जुड़े आयोजनों का हिस्सा था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके 'अंत्योदय' के विचार का उल्लेख किया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने भक्ति संगीत की इस आधुनिक प्रस्तुति को व्यापक सार्वजनिक चर्चा में ला दिया। हालांकि, 'भजन क्लबिंग' का स्वरूप स्वयं पारंपरिक भक्ति संगीत को आधुनिक मंचीय प्रस्तुति से जोड़ने वाली एक उभरती सांस्कृतिक शैली के रूप में सामने आया है।

सिक्किम में भारी भूस्खलन से तबाही, कई मकान और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त

भारतार्थ खबर Bhaaratarth.com
संवाददाता अशोक कुमार सिंह
गंगटोक, 26 सितंबर 2026। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के बीच पश्चिम सिक्किम के रिबी गांव में बड़े भूस्खलन से कई मकानों, सरकारी आवासों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना में फिलहाल किसी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खिसकने से बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की ओर आया। इसकी चपेट में आने से कई संरचनाएं प्रभावित हुईं और स्थानीय लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ गईं। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। लगातार बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा सिक्किम समेत हिमालयी क्षेत्रों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों के खिसकने का खतरा बढ़ जाता है। इससे मकानों और अन्य संरचनाओं के साथ-साथ सड़क मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। भूस्खलन के कारण सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और स्थिति के आकलन पर जोर दिया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में स्थिति पर नजर रिबी गांव में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की गतिविधियां जारी हैं और आगे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लोगों से मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने तथा जोखिम वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की जा रही है। विशेष रूप से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में स्थानीय चेतावनियों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में बारिश से बढ़ी चुनौती सिक्किम के अलावा हिमालयी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश के दौरान बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। नेपाल में भी 25 से 27 सितंबर के दौरान भारी बारिश की चेतावनी के बीच बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। बारिश का यह दौर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त सतर्कता का समय है। मौसम की स्थिति में बदलाव और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है।



गांव-शहर की दूरी घटी, ग्रामीण ढांचे में सुधार: प्रधानमंत्री मोदी

भारतार्थ खबर
Bhaaratarth.com
नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत के गांवों और शहरों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के साथ महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक भागीदारी भी बढ़ी है। उन्होंने ये बातें 25 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से गांवों और शहरों के बीच मौजूद अंतर को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने सेवा यात्रियों से अपने यात्रा अनुभवों को दर्ज करने और गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद के माध्यम से देश की विविधता तथा स्थानीय परिस्थितियों को समझने का भी आग्रह किया। ग्रामीण बदलाव और महिला

आत्मनिर्भरता पर जोर
संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में हुए बदलाव के साथ महिलाओं की बढ़ती आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में उन्होंने ऐसी पहलों का उल्लेख किया, जिनसे गांवों में आधारभूत सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि देश के विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव को निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सेवा यात्रा का उद्देश्य जनसंपर्क और सेवा
सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी और वडनगर के बीच चल रही यात्राओं में युवाओं की भागीदारी को प्रमुखता दी गई है। यात्रा के दौरान प्रतिभागी विभिन्न जिलों, कस्बों और गांवों में लोगों से संवाद करने के साथ स्वच्छता अभियान, पोषरोपण, स्वास्थ्य सहायता तथा

अन्य सेवा गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी के अनुसार, यह यात्रा 17 सितंबर से शुरू हुई है और 7 अक्टूबर तक जारी रहने का कार्यक्रम है। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों का उद्देश्य स्थानीय समुदायों से जुड़ना और सेवा गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने सेवा यात्रियों से कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उनके अनुभवों को समझना केवल यात्रा का हिस्सा नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को करीब से जानने का अवसर भी है। उन्होंने यात्रियों को अपने अनुभवों की डायरी तैयार करने की सलाह दी। ग्रामीण बुनियादी ढांचे, महिला आत्मनिर्भरता और जनभागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री के इस संवाद में विकास के साथ सामाजिक सेवा और सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिखाई दिया। सेवा यात्राओं के माध्यम से गांवों और स्थानीय समुदायों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क को अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

संपादकीय

न्यायपालिका और नागरिक अधिकार: फ़ैसलों से

आगे उनके पालन की असली परीक्षा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा केवल संविधान में अधिकार लिखे होने से सुनिश्चित नहीं होती। इन अधिकारों को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब किसी नागरिक को समय पर इलाज नहीं मिलता, जांच निष्पक्ष नहीं होती या न्याय की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती है, तब संवैधानिक अधिकारों की वास्तविक परीक्षा होती है। हाल के महीनों में सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण आदेशों ने इसी व्यापक प्रश्न को सामने रखा है कि न्यायिक निर्देशों का आम नागरिक के जीवन पर वास्तविक प्रभाव कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में गहन चिकित्सा इकाइयों यानी ICU की न्यूनतम सुविधाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी विशेष महत्व रखती है। न्यायालय ने मई 2026 में ICU के लिए तीन स्तरों कूलेवल—I, लेवल—II और लेवल—III के न्यूनतम मानकों को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्र, राज्यों और के द्रशासित प्रदेशों से इनके क्रियान्वयन की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा गया। सितंबर में न्यायालय ने 2026 के ICU दिशानिर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित समयसीमा पर भी जोर दिया। ICU केवल अस्पताल का विषय नहीं पहली नजर में ICU के न्यूनतम मानकों का मामला स्वास्थ्य प्रशासन से जुड़ा दिखाई देता है, लेकिन इसके केंद्र में नागरिक का जीवन और गरिमा है। गंभीर स्थिति में मरीज के लिए कुछ मिनटों और घंटों का अंतर भी निम्न अस्पतालों हो सकता है। ऐसे में अस्पताल में आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं नर्सिंग कर्मचारी, एम्बुलेंस और समय पर रेफरल व्यवस्था उपलब्ध होना केवल स्वास्थ्य सुविधा का प्रश्न नहीं रह जाता। सर्वोच्च न्यायालय ने, राज्यों से ICU सुविधाओं, आवश्यक मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। न्यायालय की कार्यवाही में जिला स्तर पर आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस, चिकित्सा संस्थानों के बीच समन्वय और टेली—ICU जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अदालत का निर्देश कागज से निकलकर अस्पताल तक कितनी तेजी और प्रभावशीलता से पहुंचता है। भारत जैसे विशाल देश में राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था, बजट और आधारभूत संरचना में बड़ा अंतर है। इसलिए समान मानक बनाना पहला चरण है, उन्हें जमीन पर लागू करना उससे बड़ी चुनौती है। निष्पक्ष जांच की नागरिक अधिकार न्यायपालिका की भूमिका केवल अस्पतालों की व्यवस्था तक सीमित नहीं है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में निष्पक्ष जांच नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सीधे जुड़ी है। सितंबर 2026 में कुसुमावती गौड़ा बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुराने बलात्कार—हत्या मामले में नई विशेष जांच टीम से दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। उपलब्ध न्यायिक विवरण के अनुसार अदालत ने निष्पक्ष जांच को अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा से जोड़ा। इस प्रक्रा के मामले से एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है न्याय केवल अंतिम फ़ैसला सुनाए जाने का नाम नहीं है। FIR से लेकर जांच, साक्ष्य संकलन, अभियोजन और सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय होनी चाहिए। यदि जांच ही पक्षपातपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हो जाए तो बाद की न्यायिक प्रक्रिया पर भी उसका असर पड़ सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा भी महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के सक्रिय हस्तक्षेप का उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना हो सकता है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में संस्थाओं की

समाज के विद्रूपता का दर्पण है पतिव्रता वेश्या उपन्यास

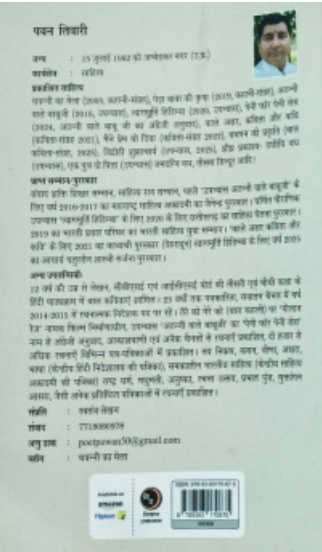


समीक्षक —लालबहादुर चौरसिया लाल, (महामंत्री— विश्व हिंदी शोध एवं संवर्धन अकादमी आजमगढ़ इकाई) 094520 88890

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com पतिव्रता वेश्या उपन्यास हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार श्री पवन तिवारी जी की सद्यः प्रकाशित कृति है। उपन्यास का शीर्षक पढ़कर मन में एक अजीब—सा प्रश्न कौंध उठता है। आखिर दो विरोधी शब्द, दो विरोधी भाव एक ही व्यक्ति या समयबद्ध निपटारा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हाल के एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में कोविड—19 अवधि से जुड़े कुछ अपेक्षाकृत कम गंभीर मामलों में अभियोजन वापस लेने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पैदा हुए ऐसे मामलों को जारी रखना आपराधिक न्याय प्रणाली और व्यापक जनहित की दृष्टि से उपयोगी नहीं होगा। यह उदाहरण बताता है कि न्यायिक प्रक्रिया में केवल कठोरता ही पर्याप्त नहीं है। परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए न्याय का संतुलित संचालन भी जरूरी है। संपादकीय दृष्टिकोण भारत में नागरिक अधिकारों की सबसे बड़ी चुनौती अब केवल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कई बार प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए इश्री दिशा में यूनिफाईड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) ऐसी तकनीकी व्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, जिसका उद्देश्य ऋणदाताओं को विभिन्न डिजिटल डेटा और सत्यापन सेवाओं से मानकीकृत तरीके से जोड़ना है। सवाल केवल यह नहीं है कि इससे कर्ज कितनी तेजी से मिलेगा, बल्कि यह भी है कि डिजिटल ऋण व्यवस्था कितनी सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी बन पाएगी।ULI का पायलट अगस्त 2023 में शुरू हुआ था। बाद में इसे व्यापक डिजिटल ऋण व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया। केंद्र सरकार के मार्च 2026 के संसदीय उत्तर के अनुसार, 27 फरवरी 2026 तक 100 ऋणदाता ULI से जुड़े थे, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक तथा NBFC शामिल थे। कर्ज की प्रक्रिया में डिजिटल पुल परंपरागत ऋण प्रक्रिया में बैंक को आवेदक की पहचान, आय, संपत्ति, क्रेडिट इतिहास और अन्य दस्तावेजों की जानकारी अलग—अलग स्रोतों से प्राप्त और सत्यापित करनी पड़ सकती है। ULI का उद्देश्य इसी बिछरी हुई व्यवस्था के बीच तकनीकी पुल उपलब्ध कराना

हमेशा रूबरू होते हैं, परंतु कह नहीं पाते। इस सच को साहित्यकार श्री पवन तिवारी जी ने बड़े ही सलीके से इस उपन्यास में वर्णित किया है। उपन्यास के नायक राज सिंह राणा हैं, जो एक ख्यातिप्राप्त चित्रकार हैं। नायिका के रूप में बबीता है, जो एक वेश्या है। बबीता के कोठे तक पहुंचने की कहानी रॉंगटे खड़ी कर देने वाली है। यही पात्र इस कहानी का प्राण—तत्व है। कोई महिला जानबूझकर वेश्या नहीं बनती। किसी महिला को वेश्यालय तक पहुंचाने में पुरुष वर्ग का ही हाथ होता है। यह बात इस कहानी से सिद्ध होती है। वह छोटी लड़की, जिसके अंदर प्रेम था, संस्कार थे, सपने थे, पूरा परिवार था, किंतु समाज ने इंटरमीडिएट की छात्रा बबीता के पंख कुतर दिए। सब कुछ रहते हुए वह लड़की आज बेबस हो गई। वह ऐसे दलदल में धकेल दी गई, जिसका जिम्मेदार पुरुष वर्ग है। किंतु जब समय ने करवट बदली, तो वही वेश्या के रूप में स्थापित स्त्री एक सच्ची पतिव्रता के रूप में स्थापित होती है। उसकी उड़ान को पंख मिलते हैं। बरसों से सुषुप्त प्रेम की रसधार फूट पड़ती है। वह सिर्फ भोग्या नहीं, शक्ति और प्रेम का पर्याय हो जाती है। राज सिंह राणा के जीवन में सब कुछ है, शक्ति प्रेम नहीं है। राणा की दो—दो शायियाँ हो चुकी हैं। लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक चल नहीं पाई। उन दोनों पत्नियों से उन्हें बहुत बड़ा

धोखा मिला। लेकिन जब बबीता उनके जीवन में आई, तो राणा की दावानि से झुलसी प्रेम की वाटिका पुनः हरी—भरी हो जाती है। पूरा उपन्यास एक वेश्या का जीवन जी रही स्त्री के पतिव्रता स्त्री बनने तक की करुण यात्रा है। पतिव्रता वेश्या उपन्यास में हमें समाज के कई कड़वे रूप देखने



को मिलते हैं, जो बिल्कुल यथार्थ लगते हैं। कोई बनावटीपन नहीं है। पूरे उपन्यास की बुनावट एक स्त्री के आंतरिक सौंदर्य की करुण गाथा है। समाज के विद्रूप चेहरे को साहित्यकार ने परत—दर—परत खोला है। वेश्यालय की दशा, सुलस—प्रशासन का चरित्र, नारी—संवेदना जैसे तमाम भाव हमें चिंतन करने पर विवश कर

देते हैं। उपन्यास के बीच—बीच में साहित्यकार श्री पवन तिवारी जी ने कुछ उपदेशात्मक वाक्यों का भी प्रयोग किया है, जो समाज को दिशा देने में कारगर सिद्ध होंगे। कितनी वैज्ञानिकता है इस वाक्य में, इसकी एक बानगी देखें— (दुख और वेदना का सम्मिश्रण हर प्रकार की आभा और उत्साह का



रावण की तरह अपहरण कर लेता है।) जब एक स्त्री दलदल में धकेल दी जाती है, तो वह फड़फड़ाती है। दलदल से निकलने का भरपूर प्रयास करती है और जब निकल नहीं पाती, तो वह टूट जाती है, निरीह हो जाती है, परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर जीने के लिए बाध्य हो जाती है। एक स्त्री की पीड़ा को साहित्यकार ने कितने

ULI: डिजिटल ऋण की दुनिया में बदलाव, आसान कर्ज के साथ भरोसे की भी परीक्षा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अब केवल पैसे के लेन—देन को आसान बनाने तक सीमित नहीं है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अगला बड़ा विस्तार ऋण और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इसी दिशा में यूनिफाईड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) ऐसी तकनीकी व्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है, जिसका उद्देश्य ऋणदाताओं को विभिन्न डिजिटल डेटा और सत्यापन सेवाओं से मानकीकृत तरीके से जोड़ना है। सवाल केवल यह नहीं है कि इससे कर्ज कितनी तेजी से मिलेगा, बल्कि यह भी है कि डिजिटल ऋण व्यवस्था कितनी सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी बन पाएगी।ULI का पायलट अगस्त 2023 में शुरू हुआ था। बाद में इसे व्यापक डिजिटल ऋण व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया। केंद्र सरकार के मार्च 2026 के संसदीय उत्तर के अनुसार, 27 फरवरी 2026 तक 100 ऋणदाता ULI से जुड़े थे, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक तथा NBFC शामिल थे। कर्ज की प्रक्रिया में डिजिटल पुल परंपरागत ऋण प्रक्रिया में बैंक को आवेदक की पहचान, आय, संपत्ति, क्रेडिट इतिहास और अन्य दस्तावेजों की जानकारी अलग—अलग स्रोतों से प्राप्त और सत्यापित करनी पड़ सकती है। ULI का उद्देश्य इसी बिछरी हुई व्यवस्था के बीच तकनीकी पुल उपलब्ध कराना

है। RBI Innovation Hub के अनुसार ULI मानकीकृत ULI के माध्यम से ऋणदाताओं को विभिन्न



डेटा सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। इसमें पहचान सत्यापन, क्रेडिट पात्रता, संपत्ति संबंधी जानकारी और शाहम संबंधी सेवाओं जैसी सुविधाएं शामिल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, MSME और वाहन ऋण जैसे ऋण—जर्नी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ULI स्वयं किसी व्यक्ति का ऋण मंजूर करता है। अंतिम ऋण निर्णय संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था के नियमों, जोखिम आकलन और पात्रता मानकों पर निर्भर करता है। यही अंतर आम तौरपर 64 अक्टूबर तक जारी है। आंकड़े बता रहे हैं बढ़ता विस्तार 31

अगस्त 2026 तक RBI Innovation Hub के आंकड़ों के अनुसार ULI पर 136 ऋणदाता,

64 सेवा प्रदाता और 143 सेवाएं लाइव थीं। अगस्त महीने में प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 2.50 करोड़ API अनुरोध संसाधित किए गए। 13 राज्यों में भूमि रिकॉर्ड सेवाएं भी उपलब्ध थीं। ये आंकड़े बताते हैं कि ULI अब केवल एक प्रयोगात्मक अवधारणा नहीं रह गया है। इसका इस्ते माल बढ़ रहा है और अलग—अलग प्रकार के ऋणदाताओं तथा डेटा सेवाओं को जोड़ने की दिशा में इसका दायरा विस्तृत हो रहा है। किसान और छोटे कारोबारियों के लिए अवसर भारत में औपचारिक ऋण तक पहुंच की सबसे बड़ी चुनौतियाँ में से एक विश्वसनीय और आसानी

से सत्यापित होने वाली जानकारी अभाव रहा है। खासकर छोटे किसान, सूक्ष्म उद्यमी और ऐसे कारोबारी जिनके पास पारंपरिक दस्तावेज सीमित हैं, उनके लिए ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। ULIमें भूमि रिकॉर्ड, क्रेडिट सूचना और अन्य डिजिटल सेवाओं तक मानकीकृत पहुंच का उद्देश्य इस समस्या को कम करना है। कृषि क्षेत्र में भूमि और संबंधित डिजिटल जानकारी, जबकि छोटे कारोबारियों के मामले में उपलब्ध वित्तीय एवं व्यावसायिक सूचनाएं ऋण मूल्यांकन को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन डिजिटल सुविधा का अर्थ अपने—आप सस्ता या हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध ऋण नहीं है। ब्याज दर, जोखिम, आय, पुनर्भुगतान क्षमता और ऋणदाता की नीतियां आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगी। सुविधा के साथ डेटा सुरक्षा की चुनौती डिजिटल ऋण की सबसे बड़ी ताकत डेटा है और यही उसका सबसे संवेदनशील पक्ष भी है। पहचान, आय, बैंकिंग गतिविधि, संपत्ति और क्रेडिट इतिहास से जुड़ी जानकारी किसी व्यक्ति की वित्तीय गोपनीयता का हिस्सा है। इसलिए डिजिटल ऋण व्यवस्था में गति के साथ सहमति, डेटा सुरक्षा और जवाबदेही को समान महत्व देना होगा। RBI की डिजिटल लेंडिंग व्यवस्था में साइबर सुरक्षा, डेटा भंडारण और ग्राहक संबंधी सूचनाओं के संरक्षण से जुड़े नियामकीय प्रावधान पहले से मौजूद हैं। यहां एक

और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या नागरिक को स्पष्ट रूप से पता होगा कि उसकी कौन—सी जानकारी, किस उद्देश्य से और किस संस्था के माध्यम से इस्ते माल की जा रही है? डिजिटल व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए इस सवाल का स्पष्ट उत्तर जरूरी है। डिजिटल खाई को भी नजरअंदाज न किया जाए भारत की डिजिटल प्रगति प्रभावशाली है, लेकिन हर नागरिक की डिजिटल क्षमता समान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों, बुजुर्गों, कम डिजिटल साक्षरता वाले लोगों और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में केवल डिजिटल प्रक्रिया पर निर्भरता नई बाधाएं भी पैदा कर सकती है। इसलिए ULI जैसी व्यवस्था को वित्तीय समावेशन का साधन बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक उन लोगों को बाहर न कर महत्वपूर्ण रहेंगी। सुविधा के साथ डेटा सुरक्षा की चुनौती डिजिटल ऋण की सबसे अधिक आवश्यकता है। डिजिटल माध्यम के साथ आवश्यक मानवीय सहायता और वैकल्पिक सेवा व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। संपादकीय प्टिकोण ULI को केवल बैंकिंग तकनीक का नया अध्याय मानना इसके व्यापक महत्व को कम करके देखा होगा। ULI ने भुगतान के क्षेत्र में डिजिटल ढांचे को नया स्वरूप दिया; ULI का उद्देश्य ऋण वितरण की प्रक्रिया को अधिक एकीकृत और सरल बनाना है। RBI के स्तर पर भी ULI को डिजिटल वित्तीय ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन किसी भी

डिजिटल व्यवस्था की सफलता केवल उसके ाम उपयोगकर्ताओंया लेन—देन की संख्या से तय नहीं होती। असली कसौटी यह होगी कि क्या छोटे किसान, सूक्ष्म कारोबारी, स्वरोजगार से जुड़े लोग और सामान्य नागरिक बिना अनावश्यक कागजी जटिलता के औपचारिक ऋण तक पहुंच बना पाते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि तेज ऋण वितरण के नाम पर जोखिम आकलन कमजोर न हो। आसान कर्ज और जिम्मेदार कर्जकू दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष भारत की डिजिटल यात्रा अद्य भुगतान से आगे बढ़कर क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर के चरण में प्रवेश कर रही है। ULI इस परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। इसके माध्यम से ऋणदाता और डिजिटल डेटा सेवाओं के बीच तकनीकी एकीकरण बढ़ने की संभावना है, जिससे ऋण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। परंतु तकनीक तभी जनहितकारी मानी जाएगी जब सुविधा के साथ पारदर्शिता, सहमति, डेटा सुरक्षा, जिम्मेदार ऋण और डिजिटल समावेशन भी सुनिश्चित हों। भविष्य की डिजिटल ऋण व्यवस्था का लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि कर्ज जल्दी मिले, बल्कि यह भी होना चाहिए कि सही व्यक्ति को सही जानकारी के आधार पर, उचित शर्तों पर और सुरक्षित तरीके से ऋण मिले। यही ULI की वास्तविक परीक्षा होगीकू डिजिटल ऋण को तेज बनाने से आगे बढ़कर उसे भरोसेमंद और समावेशी बनाना।

चुनावी गठबंधन से आगे: विधान परिषद चुनाव क्षेत्रीय राजनीति की नई तस्वीर कैसे दिखाएंगे?

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com कर्नाटक में विधान परिषद की चार सीटों के लिए होने जा रहा चुनाव केवल कुछ सीटों के लिए राजनीतिक मुकाबला नहीं है। यह चुनाव उस व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें राज्य की पाठियां अपने सं गठन, गठबंधन और सामाजिक—राजनीतिक आधार को परखती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) ने इन चारों सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में चुनावी गणित के साथ—साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि विधान परिषद जैसे सदन राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं और उनके चुनावों का राजनीतिक महत्व विधानसभा चुनावों से किस तरह अलग है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार कर्नाटक की दो

स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की जानी है, जबकि राजनीतिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें राज्य की पाठियां अपने सं गठन, गठबंधन और सामाजिक—राजनीतिक आधार को परखती हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (सेक्युलर) ने इन चारों सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में चुनावी गणित के साथ—साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि विधान परिषद जैसे सदन राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं और उनके चुनावों का राजनीतिक महत्व विधानसभा चुनावों से किस तरह अलग है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार कर्नाटक की दो

के लिए जिम्मेदारियां तय करने का निर्णय लिया है। यह समझौता केवल चुनावी सीटों के बंटवारे तक सीमित नहीं माना जा सकता। जुलाई में भी दोनों दलों ने विभिन्न चुनावों में समन्वय और भविष्य के चुनावों में साथ काम करने की दिशा में चर्चा की थी। इसलिए मौजूदा परिषद चुनाव को दोनों दलों के बीच जमीनी निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के लिए अलग चुनावी व्यवस्था है। गठबंधन का नया परीक्षण 26 सितंबर को बेंगलुरु में हुई NDA की बैठक के बाद भाजपा और जद(एस) नेताओं ने चारों सीटों पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और जद(एस) के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी समेत दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। विजयेंद्र ने कहा कि दोनों दलों ने चारों निर्वाचन क्षेत्रों में मिलकर चुनाव लड़ने और प्रत्येक सीट

के लिए जिम्मेदारियां तय करने का निर्णय लिया है। यह समझौता केवल चुनावी सीटों के बंटवारे तक सीमित नहीं माना जा सकता। जुलाई में भी दोनों दलों ने विभिन्न चुनावों में समन्वय और भविष्य के चुनावों में साथ काम करने की दिशा में चर्चा की थी। इसलिए मौजूदा परिषद चुनाव को दोनों दलों के बीच जमीनी निर्वाचन क्षेत्रों में पात्र स्नातक और शिक्षक मतदाताओं के लिए अलग चुनावी व्यवस्था है। गठबंधन का नया परीक्षण 26 सितंबर को बेंगलुरु में हुई NDA की बैठक के बाद भाजपा और जद(एस) नेताओं ने चारों सीटों पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और जद(एस) के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी समेत दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। विजयेंद्र ने कहा कि दोनों दलों ने चारों निर्वाचन क्षेत्रों में मिलकर चुनाव लड़ने और प्रत्येक सीट

प्रतिनिधित्व का अवसर देते हैं। इसके अलावा परिषद में स्थानीय निकायों और अन्य निर्धारित निर्वाचन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी प्रतिनिधित्व आता है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य विभायी प्रक्रिया में अलग—अलग सामाजिक और पेशेवर समूहों की आवाज को स्थान देना है। इसलिए परिषद चुनाव को केवल राजनीतिक दलों के बीच सीटों की लड़ई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह चुनाव यह भी तय करता है कि शिक्षकों, शिक्षित पेशेवरों और संबंधित मतदाता समूहों से जुड़े मुद्दे विभायी मंच तक किस रूप में पहुंचेंगे। मु्दा केवल दलों का नहीं, मतदाताओं का भी राजनीतिक विश्लेषण है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सामान्य विधानसभा चुनाव की तरह केवल एक ही प्रकार के मतदाता नहीं होंगे। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र समाज के विशिष्ट मतदाता समूहों को राजनीतिक

से खर्च में सावधानी की सलाह को वित्तीय प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे होते हैं। इसलिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी होगा कि वे केवल व्यवस्था का मूल उद्देश्य विभायी प्रक्रिया में अलग—अलग सामाजिक और पेशेवर समूहों की आवाज को स्थान देना है। इसलिए परिषद चुनाव को केवल राजनीतिक दलों के बीच सीटों की लड़ई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह चुनाव यह भी तय करता है कि शिक्षकों, शिक्षित पेशेवरों और संबंधित मतदाता समूहों से जुड़े मुद्दे विभायी मंच तक किस रूप में पहुंचेंगे। मु्दा केवल दलों का नहीं, मतदाताओं का भी राजनीतिक विश्लेषण है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सामान्य विधानसभा चुनाव की तरह केवल एक ही प्रकार के मतदाता नहीं होंगे। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र समाज के विशिष्ट मतदाता समूहों को राजनीतिक



बेंगलुरु, रविवार , 27 सितम्बर 2026

प्रादेशिक समाचार

Bhaarataarth.com

4

KYC की पहली धार्मिक यात्रा में कुक्के सुब्रमण्या, धर्मस्थल और सौथड्का महागणपति के दर्शन



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 26 सितंबर 2026।
खंडेलवाल युवा चौप्टर बेंगलुरु (KYC), की ओर से आध्यात्मिक एवं सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार दो दिवसीय धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान सदस्यों ने

कर्नाटक के धर्मस्थल क्षेत्र और आसपास स्थित प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर परिवार, समाज और सभी सदस्यों के सुख-शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामना की। यात्रा के दौरान श्री कुक्के सुब्रमण्या स्वामी मंदिर, श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर, धर्मस्थल और सौथड्का श्री महागणपति मंदिर में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए गए।



प्रतिभागियों ने मंदिरों में पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक शांति और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। प्रमुख तीर्थस्थलों के किए दर्शन कुक्के सुब्रमण्या स्वामी मंदिर कर्नाटक के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है और भगवान सुब्रमण्या की आराधना के लिए श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है। वहीं श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिर, धर्मस्थल दक्षिण

भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में अपनी धार्मिक परंपरा और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यात्रा में सौथड्का श्री महागणपति मंदिर के भी दर्शन किए गए। प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित इस धार्मिक स्थल पर सदस्यों ने भगवान महागणपति की आराधना कर सभी के लिए मंगलकामना की। चार सदस्यों ने की

के.आर. मार्केट में सफाई और सुविधाओं पर सख्ती, बकाया किराएदारों को 15 दिन की मोहलत

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 26 सितंबर 2026। बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन के चामराजपेट डिवीजन स्थित के.आर. मार्केट में सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने, बिजली व्यवस्था, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगम ने सख्त रुख अपनाया है। कमिश्नर जगदीश जी. ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बाजार की व्यवस्थाओं में तेजी लाने और नागरिकों व व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सफाई और कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर के आर. मार्केट में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होने को देखते हुए कमिश्नर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र में कचरा लंबे समय तक जमा नहीं रहना चाहिए। अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन पूरे बाजार क्षेत्र की नियमित सफाई करने तथा जरूरत पड़ने पर दो से तीन शिफ्ट में सफाई व्यवस्था संचालित करने को कहा गया। सफाई के बाद एकत्र कचरे के उचित परिवहन और निस्तारण की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। फुटपाथों पर दोबारा कब्जे पर कार्रवाई समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि पहले अतिक्रमण मुक्त कराए गए कुछ फुटपाथों पर दोबारा दुकानें और सामान रखकर कब्जा किया गया है। कमिश्नर ने ऐसे

अतिक्रमण तत्काल हटाने तथा दोबारा कब्जा रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैदल यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए फुटपाथों को खाली रखना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिजली और शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश कमिश्नर ने बाजार में बिजली कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट और अन्य विद्युत व्यवस्था की जांच कराने तथा कमियां मिलने पर तत्काल मरम्मत एवं रखरखाव कराने को कहा। इसके साथ ही खराब या अनुपयोगी शौचालयों की पहचान कर आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बाजार के शौचालय साफ, चालू और व्यापारियों तथा आम नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। तय बैंडिंग क्षेत्र से बाहर कारोबार पर सख्ती के.आर. मार्केट के सामने व्यापारियों के लिए निर्धारित बैंडिंग क्षेत्र पहले से चिह्नित हैं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित क्षेत्र के बाहर कारोबार कर सड़क अथवा सार्वजनिक आवागमन नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आवश्यकता के अनुसार ऐसे अतिक्रमण हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए। टूटी टाइल्स और सीढ़ियों की होगी मरम्मत बाजार में खराब और टूटी हुई फर्श की टाइल्स की पहचान कर उनकी मरम्मत अथवा आवश्यकता के अनुसार

नई टाइल्स लगाने को कहा गया। इसके अलावा सीढ़ियों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत या बदलाव कराने के निर्देश दिए गए, ताकि व्यापारियों और नागरिकों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे। जलमराव की समस्या का स्थायी समाधान के.आर. मार्केट के पतेदार सब्जी बाजार क्षेत्र में पानी और गंदा पानी जमा होने से कीचड़ की समस्या सामने आने पर कमिश्नर ने इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने जरूरत वाले स्थानों पर कंकीटिंग, उचित ढलान और प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि पानी का ठहराव कम हो और बाजार क्षेत्र में स्वच्छता एवं आवागमन की स्थिति बेहतर हो सके। बकाया किराए के लिए 15 दिन की समयसीमा के.आर. मार्केट की दुकानों और स्टॉल का किराया बकाया रखने वाले व्यापारियों को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। कमिश्नर ने कहा कि निर्धारित अवधि में किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ निगम के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकानों पर ताला लगाने और उन्हें सिटी कॉर्पोरेशन की अभिरक्षा में लेने की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। बैठक में डेवलपमेंट एडिशनल कमिश्नर केंद्रचलपति आर, ज्वाइंट कमिश्नर सनान्ध के. और हेमंत शरण, चीफ इंजीनियर विजय कुमार हरिदास, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कंशेश्वर, कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

विधान परिषद की चार सीटों पर BJP-JDS साथ, विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
बेंगलुरु, 26 सितंबर 2026।
कर्नाटक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेकुलर) यानी JDS ने चार सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने शनिवार को बेंगलुरु में BJP-JDS नेताओं की बैठक के बाद यह जानकारी दी। चुनाव आयोग के अनुसार, चार परिषद सीटों के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को होगा है। इनमें दो स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। विजयेंद्र ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, एच. डी. कुमारस्वामी सहित दोनों दलों के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच चारों सीटों पर समन्वय के साथ चुनाव लड़ने को लेकर सहमति

बनी है और प्रत्येक सीट के लिए जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई। चार सीटों पर चुनावी समन्वय जिन चार निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होगा है, उनमें कर्नाटक दक्षिण-पूर्व स्नातक, कर्नाटक पश्चिम स्नातक, कर्नाटक उत्तर-पूर्व शिक्षक और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। उपलब्ध चुनावी जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से JDS ने ए.पी. रंगनाथ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के मौजूदा सदस्य पुट्टन्ना इस सीट से चुनाव मैदान में हैं। अन्य तीन सीटों पर भी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। विजयेंद्र ने कहा कि BJP और JDS आने वाले दिनों में आपसी समन्वय के साथ चुनावी रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने इसे राज्य में NDA

के स्तर पर दोनों दलों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया। कांग्रेस सरकार पर प्रशासन और वित्त को लेकर आरोप बैठक के बाद विजयेंद्र ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों का मुख्यमंत्री के नेतृत्व को लेकर भरोसा कम हुआ है और सरकार का प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है। हालांकि, ये विजयेंद्र के राजनीतिक आरोप हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार की ओर से वित्तीय स्थिति को लेकर यह कहा गया है कि वित्त विभाग की ओर से खर्च में सावधानी बरतने की सलाह को राज्य के दिवालिया होने या धनराशि समाप्त होने के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा है कि वित्त विभाग का दायित्व बहुत और वित्तीय सीमाओं के भीतर खर्च सुनिश्चित करना है। वित्त विभाग की चिट्ठी बनी राजनीतिक मुद्दा वित्तीय स्थिति को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच हाल के दिनों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हुए हैं। कर्नाटक वित्त विभाग ने बड़े व्यय वाली नई परियोजनाओं को लेकर सीमित वित्तीय गुंजाइश का उल्लेख करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी थी।

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 26 सितंबर 2026।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आ्युक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए SIR प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से पुनरीक्षण कराने की मांग रखी। उनकी ये मांगें जारी राजनीतिक विवाद के बीच सामने आई हैं। निर्वाचन आयोग पर लगाए गंभीर आरोप सभा को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने आयोग को भाजपा के प्रति पक्षपाती बताते हुए दावा किया कि गरीबों और सरकार की आलोचना करने वाले मतदाताओं के नाम प्रभावित किए जा रहे हैं। ये आरोप मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मंच से लगाए हैं और इन्हें परियोजनाओं को लेकर सीमित वित्तीय गुंजाइश का उल्लेख करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी थी।

निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों की समीक्षा की मांग की। शिवकुमार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इस

SIR के तहत 30 जून 2026 से घर-घर मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस समय राज्य में करीब 5.54 करोड़ मतदाता दर्ज थे। मसौदा



मुद्दे पर संसद में चर्चा करानी चाहिए। SIR को रद्द कर नए सिरे से प्रक्रिया की मांग मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में चल रही SIR प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से पुनरीक्षण कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए चुनावी आंकड़ों की व्यापक समीक्षा और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। इसी तरह की मांग उन्होंने इससे पहले भी उठाई थी। कर्नाटक में

मतदाता सूची में 4.46 करोड़ मतदाता 24 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में कर्नाटक में 4,46,80,151 मतदाता दर्ज किए गए। इससे पहले 16 जून को मतदाता सूची में 5,54,32,314 मतदाता थे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1.07 करोड़ से अधिक मतदाताओं को Absent, Shifted, Dead Duplicate और Others (ASDDO) श्रेणी में रखा गया था।

राजस्थान में आवारा पशुओं से फसल बचाने में कारगर तारबंदी योजना

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

धौलपुर, 26 सितंबर 2026।
राजस्थान में आवारा पशुओं और नीलगाय से फसलों को होने वाला नुकसान किसानों के लिए लंबे समय से बड़ी चुनौती बना हुआ है। खेत में दिन-रात मेहनत के बाद तैयार की गई फसल यदि पशुओं के झुंड से नष्ट हो जाए तो किसान को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। ऐसे में खेत की तारबंदी फसल सुरक्षा का एक व्यावहारिक उपाय बनकर सामने आई है। धौलपुर जिले के पिपरीवा गांव के किसान रामवीर सिंह के अनुभव को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवारा पशुओं और नीलगाय से बार-बार फसल को नुकसान होने के बाद उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क कर तारबंदी योजना के तहत और सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है।

में तारबंदी कराई गई। तारबंदी से फसल को मिली सुरक्षा रामवीर सिंह के अनुसार, पहले पशुओं के खेत में प्रवेश करने से फसल को काफी नुकसान



होता था। कई बार उत्पादन इतना प्रभावित होता था कि खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता था। तारबंदी के बाद खेत में बाहरी पशुओं का प्रवेश काफी हद तक रुक गया और फसल को सुरक्षित रखने में मदद मिली। उनका कहना है कि फसल के नुकसान में कमी आने से उत्पादन और कृषि आय में भी सकारात्मक असर पड़ा। रामवीर सिंह की कहानी आसपास के किसानों के लिए भी खेत की सुरक्षा के वैकल्पिक

उपायों पर विचार करने का उदाहरण बनी है। तारबंदी योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान कृषि विभाग की तारबंदी संबंधी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य नीलगाय, आवारा पशुओं और अन्य जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को कम करना है। सरकारी दिशा-निर्देशों में कांटेदार अथवा चेनलिक तारबंदी को फसल सुरक्षा के उपाय के रूप में शामिल किया गया है। राज किसान साथी पोर्टल पर वर्तमान में कृषि विभाग की सेवाओं में खेतों की तारबंदी का विकल्प उपलब्ध है। विभाग ने अनुदान योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। कितनी मिल सकती है आर्थिक सहायता? राजस्थान कृषि विभाग के पूर्व आधिकारिक दिशा-निर्देशों में तारबंदी के लिए प्रति किसान अधिकतम 400 रिंगी मीटर तक लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान दर्ज है।